Profits and Losses of Central Warehousing Corporation

818. SHRI BALBIR SINGH : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) what are the profits or losses of the Central Warehousing Corporation for the last three years; and

(b) whether the said Corporation is still necessary in view of the changed policy about Public Sector Undertakings ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) The net profit earned by the Central Warehousing Corporation during the last 3 years is as under :—

Year	Net profit after tax (Rs. in lakhs)
1989-90	4048.55
1990-91	4346.78
1991-92	4208.83

(b) Yes, Sir.

उत्तर प्रदेश में गन्ना-उत्पादकों को देय बकाया राशि

819. **श्री वीरेन जे. शाह :**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित चार चीनी मिलों की ओर गन्ना-उत्पादकों की लगभग 937.94 लाख रुपये की राशि बकाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से गन्ना-उत्पादकों को तुरन्त इस राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर-प्रदेश में कोई भी चीनी मिल संचालित नहीं की जा रही है । तथापि, उत्तर प्रदेश में चार चीनी मिलें निगम/कंपनी द्वारा चलाई जा रही हैं जिसमें केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण शेयर भागीदारी है । इन चार मिलों से संबंधित गन्ना कीमत के बकाया की स्थिति विवरण में दी गई है **(नीचे देखिए)** ।

(ख) से (घ) गन्ना कीमत के बकाया का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है जिसके पास किसानों को गन्ना कीमत के बकाया के भुगतान के लिए बाध्य करने हेतु आवश्यक शक्तियां तथा क्षेत्रीय अभिकरण हैं ।

तथापि, इन चार मिलों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुरोध को वस्त्र मंत्रालय को भेज दिया गया है जो उक्त चीनी मिलों को चलाने वाले निगम/कंपनी का प्रशासनिक मंत्रालय है ।

विवरण

क्रम सं.	द्वारा चलाई जा रही चीनी मिलें	मिल का नाम	गन्ना कीमत का बकाया (रु०/लाख)	मिल द्वारा सूचित की गई स्थिति ——को
1	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	पदरौना	693.12	15-5-1992
2	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	काठकूईयां	192.59	15-10-1992
3	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	गौरीबाजार	164.59	31-10-1992
4	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन	आनन्दनगर	302.27	15-10-1992

Setting up of 16 new Sugar Mills in Uttar Pradesh

820. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether it is a fact that licence for setting up of sixteen new sugar Mills in Uttar Pradesh and transfer of three licences from co-operative sector to private/joint sector is pending with the Central Government;

(b) if so, what action has been taken in this regard; and

(c) what are the reasons for delay in decision ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) In view of the large pendency of unimplemented letters of intent/licences already issued, proposals for setting up of new sugar factories have not yet been taken up for consideration.

However, in respect of 3 proposals for transfer of letters of intent/industrial licences from cooperative sector to private/joint sector, State Government of Uttar Pradesh have been requested to furnish analytical comments on each proposal.

Requirement of Wheat under Public Distribution System

821. SHRI PRAMOD MAHAJAN : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) the quantity of wheat needed for the country under Public Distribution System this year;

(b) the quantity of wheat to be imported this year;

(c) what are the reasons for such an import; and

(d) what are the rates tendered for import from different countries, country-wise ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) A quantity of approximately 9 million tonnes of wheat may be needed for the Public Distribution System during the year 1992-93.

(b) to (d) Contracts for import of 2.99 million tonnes of wheat have been signed. This has been done in order to increase the domestic availability and bridge the gap between demand and supply occasioned due to an estimated drop of about 9 million tonnes in the production of foodgrains during the crop year 1991-92, thereby preventing sharp rise in the wheat prices during the lean season. This will also enable the Government to maintain required supplies of wheat for the Public Distribution System in States and Union Territories, including the revamped PDS launched in about 1700 blocks covering